



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2016/फाल्गुन 6, 1937

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2016/PHALGUNA 6, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 फरवरी, 2016

**सं. टीएमपी/14/2016-विविध.**—पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी दिनांक 3 फरवरी 2016 द्वारा जारी किए गए संप्रेषण के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के दरमानों में एक सामान्य शर्त शामिल करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/14/2016-विविध

आदेश

(फरवरी 2016 के 9वें दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार ने अपने संप्रेषण सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी दिनांक 3 फरवरी 2016 द्वारा इस प्राधिकरण को संप्रेषित किया गया है कि सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों द्वारा नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट के साथ-साथ कार्गो एवं पोत संबंधित सेवाओं के लिए कम प्रभारों के निर्धारण हेतु सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों को निदेश जारी करे।

2. उक्त पत्र में एमओएस ने कहा है कि:

- (i). “कारोबार करना आसान बनाना – सीमाओं के पार व्यापार” पर 23 दिसम्बर 2015 को हुई सचिवों की समिति की बैठक के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:  
“पोत परिवहन मंत्रालय और राजस्व विभाग पणधारियों द्वारा नियमित घंटों के बाद निर्यातकों/आयातकों को प्रदत्त सेवाओं हेतु प्रभार कम करने के लिए उचित कदम उठाए।”
- (ii). पत्तनों में भीड़ कम करने के लिए, नियमित घंटों के बाद निर्यातकों और आयातकों को प्रदत्त कार्गो एवं पोत संबंधित सेवाओं के लिए पृथक कम प्रभार निर्धारित करने की जरूरत है। हालांकि महापत्तन प्रचालनात्मक सेवाएं चौबीसों घंटे होती हैं और नियमित घंटों के दौरान कोई प्रीमियम वसूल नहीं कर सकता, परन्तु यह जरूरी है कि नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करने हेतु पत्तन प्रभारों में छूट दी जाए।

- (iii). महापत्तनों/बीओटी प्रचालकों द्वारा नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूटों एवं कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं हेतु कम प्रभारों के निर्धारण की जांच की जाए और इस संबंध में लिए गए निर्णय का अनुपालन करने के लिए महापत्तनों/बीओटी प्रचालकों को निदेश जारी किया जाए।

3.1. यह उल्लेखनीय है कि (तत्कालीन) पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.16.1. जोकि वर्तमान में महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों पर लागू है और महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण हेतु एमओएस द्वारा जारी प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 8.1. के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है कि दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। पत्तन न्यास और बीओटी प्रचालक निम्नतर दरें वसूल कर सकते हैं और/अथवा उच्चतर रियायतें तथा छूट स्वीकृत कर सकते हैं। यह शर्त सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों के दरमानों में पहले ही एकसमान रूप से निर्धारित की गई है।

3.2. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। इस प्रकार पत्तन न्यास और बीओटी प्रचालकों को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों की अपेक्षा कम दरें वसूल करने और/अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रियायतों/छूटों की अपेक्षा अधिक रियायतें तथा छूट स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

3.3. इस प्राधिकरण को जारी किए गए दूसरे कार्यालय ज्ञापन सं. पीडी-14033/1/101/2015-पीडी.वी दिनांक 8 जनवरी 2015 में यथा दर्ज, समग्र मात्राओं/टर्नओवर में वृद्धि नियमित घंटों के बाद सेवाओं हेतु छूट ऑफर करने के लिए सभी पणधारियों हेतु व्यवहार्य प्रस्ताव बनाते हुए नियमित घंटों के बाद सेवाओं के लिए कम किए गए प्रभारों हेतु क्षतिपूर्ति करेगा। इससे निर्यात/आयात में समय तथा लागत में काफी कटौती होगी।

4. 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.2.6 और प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.5 के अनुसरण में इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्य दिशानिर्देशों के खंड 3.6 के अनुसार, सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेश को कार्यान्वित करने के लिए परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। एमओएस का निदेश इस प्राधिकरण पर बाध्यकारी है तथा तत्काल अनुपालन की अपेक्षा करता है।

5. इस अवस्था में नियमित घंटों के बाद महापत्तन न्यासों तथा वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु पृथक दर का निर्धारण करने में समय लगेगा। सभी महापत्तन न्यासों और बीओटी प्रचालकों के पास कम दरें वसूल करने अथवा अधिक छूट ऑफर करने का अधिकार पहले से उपलब्ध होने के मद्देनजर, यह उचित पाया गया है कि महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों, जो 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन शासित हैं, के मौजूदा दरमानों में एक सामान्य शर्त के रूप में एमओएस द्वारा जारी किए निदेश का निर्धारण किया जाए।

6.1. एमओएस के हाल ही के निदेश का कार्यान्वयन करने के लिए तथा उक्त निदेश के पीछे के आशय को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मौजूदा दरमानों में निम्नलिखित सामान्य शर्त निर्धारित करता है:

“पत्तनों में भीड़ कम करने के लिए और नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करने हेतु, नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए कार्गो एवं पोत संबंधित सेवाओं के लिए निम्नतर प्रभार वसूल किए जाएंगे एवं विशेष छूट ऑफर की जाएगी।”

*“पत्तनों में भीड़ कम करने के लिए और नियमित घंटों के बाद पत्तन सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करने हेतु, नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए कार्गो एवं पोत संबंधित सेवाओं के लिए निम्नतर प्रभार वसूल किए जाएंगे एवं विशेष छूट ऑफर की जाएगी।”*

6.2. सामान्य शर्त तत्काल प्रभावी होगी।

7. 2015 की प्रशुल्क नीति द्वारा शासित सभी महापत्तन न्यासों और 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित वहां पर प्रचालन करने वाले बीओटी प्रचालकों को, तदनुसार, उनके दरमान संशोधित करने का निदेश दिया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/15]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 16th February, 2016

**No. TAMP/14/2016-Misc.**—In compliance of a communication issued by the Ministry of Shipping, Government of India vide its letter No PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby inserts a general

conditionality in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and the Private Terminals operating thereat, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/14/2016-Misc.

## **ORDER**

(Passed on this 9th day of February, 2016)

The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No. PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016 has communicated to this Authority to issue directions to all the Major Port Trusts and BOT Operators operating thereat for prescription of lower charges for cargo & vessels related services as well as special discount in port charges for the services rendered after regular hours by the Major Port Trusts and BOT Operators operating thereat.

2. The MOS in the said letter has stated that :

- (i). During the Committee of Secretaries Meeting held on 23 December 2015 on “Ease of doing business- Trading Across Borders”, the following decision inter-alia was taken:

*“Ministry of Shipping and Department of Revenue may take appropriate steps for reducing charges for services rendered to exporters / importers after regular hours by stakeholders.”*

- (ii). In order to decongest the ports, it is necessary to prescribe separate lower charges for cargo and vessel related services rendered to exporters and importers after regular hours. Though Major Ports operational services round the clock and do not charge any premium during the regular hours, it is necessary to give discount in port charges to encourage exporters / imports to utilise the port services beyond regular hours.
- (iii). Prescription of lower charges for cargo and vessel related services as well as special discounts in port charges for the services rendered after regular hours by the Major Ports / BOT operators may be examined and direction may be issued to the Major Ports / BOT Operators to comply with the decision taken in this regard.

3.1. It is noteworthy that as per Clause 2.16.1. of the Tariff Guidelines of 2005 issued by the (then) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways which is presently applicable to the BOT operators operating in Major Port Trusts and as per clause 8.1. of the Tariff Policy 2015, issued by the MOS for tariff determination of Major Port Trusts stipulate that the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trusts and BOT operators can charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts. This condition is already uniformly prescribed in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

3.2. Thus, it can be seen that the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trust and BOT operators thus already have the flexibility to charge lower rates than the rates approved by this Authority and / or allow higher rebates and discounts than the rebates / discounts approved by this Authority.

3.3. As recorded in another Office Memorandum No. PD-14033/1/101/2015-PD.V dated 8 January 2015 issued to this Authority, increase in overall volumes / turnover could compensate for reduced charges for services after regular hours making it a viable proposition for all stakeholders to offer discounts for services after regular hours. This could lead to considerable reduction in time and cost to export / import.

4. As per clause 3.2.6. of the tariff guidelines of 2005 and clause 3.6 of the Working Guidelines issued by this Authority in pursuance of clause 1.5. of the Tariff Policy 2015, consultative process is not required to be followed to implement the policy directive issued by the Government. The direction of the MOS is binding on this Authority and requires immediate compliance.

5. Prescription of separate rate for the services rendered by Major Port Trusts and BOT operators operating thereat after regular hours at this stage will be time consuming. In view of the flexibility already available with all the Major Port Trusts and BOT operators to charge lower rates or offer higher discounts, it is found appropriate to prescribe the

direction issued by the MOS in the form of a general conditionality in the existing Scale of Rates of the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat who are governed under the tariff guidelines of 2005.

6.1. In order to implement the recent direction of the MOS and bearing in mind the intention behind the said direction, this Authority decides to prescribe the following general conditionality in the existing Scale of Rates of all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat approved by this Authority:

*“In order to decongest the ports and encourage exporters / importers to utilize the port services beyond regular hours, lower charges will be levied for cargo and vessels related services as well as special discount will be offered in port charges for the services rendered after regular hours.”*

6.2. The general conditionality will come into force immediately.

7. All the Major Port Trusts governed by the Tariff Policy of 2015 and BOT operators operating thereat governed by the Tariff guidelines of 2005 are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/15]